राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

कुंबले को बनाया जाए भारतीय टीम का मुख्य चयनकर्ता : सहवाग
>> 15

वर्ष 3 अंक 73

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 22 अगस्त 2019

www.jagran.com
पृष्ठ 16

27 घंटे की लुकाछिपी के बाद चिदंबरम गिरफ्तार

कार्रवाई ▸ आवास पर आधे घंटे पूछताछ के बाद सीबीआइ ने गिरफ्त में लिया, जांच अधिकारी ले गए मुख्यालय, आज सुबह होगी कोर्ट में पेशी

अब पूर्व केंद्रीय मंत्री को नए सिरे से निचली अदालत में देनी होगी जमानत अर्जी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लगभग 27 घंटे की लुकाछिपी के बाद आखिरकार पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सीबीआइ ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद से ही चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने की हरसंभव कोशिश भी की और तब तक के लिए भूमिगत भी रहे, लेकिन राहत मिलने में देरी होने और कानून के डर से भूमिगत होने के लग रहे आरोपों को देखते हुए चिदंबरम ने सामने आने का फैसला किया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में उनके सामने आते ही सीबीआइ और ईडी की टीमों ने उनके आवास पर पहुंचकर आधे घंटे तक पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सीबीआइ मुख्यालय ले जाया गया और गुरुवार सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। चिदंबरम को अब नए सिरे से जमानत की अर्जी लगानी पड़ेगी।

दरअसल, सीबीआइ और ईडी मंगलवार को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद चिदंबरम की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई थीं। इसके लिए सीबीआइ और ईडी की टीमें उनके जोरबाग स्थित घर पर भी पहुंचीं और पूछताछ के लिए हाजिर होने का नोटिस भी चस्पा किया, लेकिन बुधवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद में चिदंबरम ने भूमिगत रहना ही पसंद किया। मोबाइल बंद कर दिया, सुरक्षाकर्मी और गाड़ी छोड़ दी। सीबीआइ और ईडी की टीमें उनके ड्राइवर से पूछताछ करती रहीं, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इस बीच विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले में आलोचना झेल चुकी सीबीआइ और ईडी ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया ताकि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं जा सकें।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आखिरकार पी. चिदंबरम ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेस कर अपनी सफाई दी और कानून का सामना करने का भरोसा दिया। वहां से जैसे ही चिदंबरम जोरबाग स्थित अपने घर पहुंचे, सीबीआइ और ईडी की टीमें भी वहां धमक पड़ीं। वैसे मीडिया और चिदंबरम समर्थकों की मौजूदगी के कारण सीबीआइ टीम को चिदंबरम के घर के भीतर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दीवार फांदकर वे किसी तरह भीतर पहुंचीं और चिदंबरम से पूछताछ शुरू की। हाईप्रोफाइल ड्रामे को देखते हुए सीबीआइ के 30 अफसरों की टीम चिदंबरम के घर पर मौजूद थी। चिदंबरम जैसे बड़े नेता से पूछताछ और गिरफ्तारी को देखते हुए सीबीआइ ने संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को भेजा था। यही नहीं, हालात संभालने के लिए दिल्ली पुलिस को भी बुला लिया गया था। चिदंबरम के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी और नारेबाजी के बाद उन्हें हटाने में दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि देर रात चिदंबरम का मेडिकल कराया गया। गुरुवार को उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि वहां सीबीआइ रिमांड की मांग करेगी।

दरअसल, पी. चिदंबरम आइएनएक्स मीडिया मामले में लंबे समय से गिरफ्तारी को टालते आ रहे थे। मार्च 2017 में एफआइआर दर्ज करने के बाद 2018 की शुरुआत में ही ईडी और सीबीआइ ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब करना शुरू कर दिया था। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए चिदंबरम ने पहले ही ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। जांच एजेंसियां उन्हें बार-बार बुलाती रही और वह अग्रिम जमानत की अवधि बढ़वाते रहे। ट्रायल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की अवधि को 27 बार बढ़ाया। ईडी और सीबीआइ ने अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी और आखिरकार मंगलवार को जांच एजेंसियों की कोशिश सफल हुई और चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत का सुरक्षा चक्र खत्म हो गया।

नई दिल्ली में बुधवार को सीबीआइ ने आइएनएक्स मीडिया मामले में आरोपों का सामना कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। चिदंबरम को कार से अपने दफ्तर ले जाते जांच एजेंसी के अधिकारी। प्रेट्र

यूं चला घटनाक्रम

- रात 8:00 बजे- चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे
- रात 8:15 बजे- चिंदबरम कांग्रेस मुख्यालय से घर के लिए निकले
- रात 8:37 बजे- चिंदबरम दिल्ली के जोरबाग वाले घर पहुंचे
- रात 8:40 बजे- सीबीआइ की टीम चिदंबरम के घर पहुंची
- रात 8:44 बजे- सीबीआइ टीम दीवार फांदकर घर में घुसी
- रात 8:50 बजे- ईडी की टीम भी चिदंबरम के घर पहुंची

यह है मामला

आइएनएक्स मीडिया के मामले में केवल चार करोड़ रुपये विदेशी निवेश का एफआइपीबी क्लीयरेंस दिया गया था। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी 305 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश ले आए। एफआइपीबी और आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस गड़बड़ी को पकड़ लिया था और कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन इस बीच इंद्राणी मुखर्जी ने कार्ति चिदंबरम के मार्फत पी. चिदंबरम से दिल्ली के हयात रेजेंसी में मुलाकात की। सरकारी गवाह बनी इंद्राणी मुखर्जी ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज अपने बयान में बताया कि पी. चिंदबरम ने उन्हें कार्ति के संपर्क में रहने का निर्देश दिया। इसके बाद कार्ति से जुड़ी कंपनियों में पैसे दिए गए और पी. चिदंबरम ने आइएनएक्स मीडिया में निवेश पर एफआइपीबी की मुहर लगवा दी।

कुछ गलत नहीं किया, झूठा फंसाया गया : चिदंबरम

नई दिल्ली : पी. चिदंबरम बुधवार शाम करीब 27 घंटे बाद कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया के सामने आए। उन्होंने छिपे होने की खबर को गलत बताते हुए कहा, जिन्हें झूठ बोलने की बीमारी है वो यह झूठा प्रचार कर रहे थे। बीते चौबीस घंटों के दौरान वे अपने वकीलों के साथ 'न्याय की तलाश' के लिए कानूनी याचिका तैयार कर रहे थे। चिदंबरम ने कहा, आइएनएक्स मीडिया मामले में उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। न ही एफआइआर में उनका नाम है, मगर प्रतिशोध की राजनीति में उन्हें झूठा फंसाया गया है। कानून में उनकी पूरी आस्था है और जीवन तथा स्वतंत्रता में किसी को चुनना पड़ा तो वे स्वतंत्रता को चुनेंगे। (पेज-3)

राहुल-प्रियंका बोले, एजेंसियों की मदद से किया जा रहा चरित्र हनन

नई दिल्ली : कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने दिग्गज नेता के समर्थन में उतर आया है। राहुल गांधी ने सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर चिदंबरम का चरित्रहनन हनन करने का आरोप लगाया है। वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि चिदंबरम सत्ता की नाकामियों को बिना डरे सामने लाते रहे हैं इसीलिए सरकार शर्मनाक तरीके से उनके पीछे पड़ी है। चिदंबरम के खिलाफ सीबीआइ-ईडी की अतिसक्रियता के मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कानूनी लड़ाई के अलावा आगे की राजनीतिक लड़ाई की रणनीति पर भी मंत्रणा शुरू कर दी है। (पेज-3)

भ्रष्टाचार पर वार

बचाव के लिए दौड़ते रहे वरिष्ठ वकील, नहीं मिली राहत पेज>>3
माल्या-नीरव मोदी जैसी हरकतें कर रहे चिदंबरम : भाजपा पेज>>3

सरोकार

पर्यावरण से यारी, 21 साल से साइकिल की सवारी

शाहजहांपुर : पर्यावरण संरक्षण की खातिर उन्होंने पेट्रोल-डीजल के वाहनों में सफर करना छोड़ दिया। 21 साल हो गए, जहां भी जाते हैं, साइकिल से। उप्र के शाहजहांपुर जिले के 64 वर्षीय सुरेश मिश्रा की कहानी। (पेज-10)

जागरण विशेष

झारखंड में हरियाली की जीत का जश्न मना रहीं तितलियां

रांची : झारखंड के पिपरवार में कोयला खनन से बंजर हो चुके 25 हेक्टेयर क्षेत्र में आज ईको पार्क लहलहा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र फिर विकसित हो चुका है। सैर-सपाटे के साथ अध्ययन का भी केंद्र बन चुकी है कायाकल्प वाटिका। (पेज-10)

उप्र में योगी ने किया मंत्रिमंडल विस्तार, 18 नए चेहरे शामिल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब ढाई वर्ष बाद बुधवार को मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छह कैबिनेट, छह स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्यमंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले कुल 23 लोगों में 18 चेहरे नये हैं। (पेज-4)

केरेबियाई चुनौती
टेस्ट सीरीज
वेस्टइंडीज 28 भारत
शाम 7:00 बजे से
स्थान : एंटीगा
प्रसारण : सोनी नेटवर्क

अब डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर की समस्या को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- फिर की मध्यस्थता की बात, कहा कश्मीर में हिंदू-मुस्लिम साथ नही रह पा रहे
- भारत ने नहीं जताई प्रतिक्रिया, सप्ताहांत में मोदी-ट्रंप मुलाकात संभव

अपने बयानों से अपनी ही सरकार के लिए कई बार शर्मिंदगी का कारण बनने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कश्मीर पर बेहद बेतुकी बयानबाजी की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को निकालने की मशक्कत में ट्रंप ने ना सिर्फ कश्मीर में मध्यस्थता करने की बात की बल्कि इसे हिंदू-मुस्लिम धर्म से जोड़ने का सनसनीखेज बयान दे डाला। पिछले एक पखवाड़े में कश्मीर में मध्यस्थता करने का यह ट्रंप का तीसरा बयान है। यह बयानबाजी तब की गई है जब पिछले हफ्ते ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कश्मीर मुद्दे को भारत व पाक को ही सुलझाना होगा। भारत ने भी स्पष्ट किया है कि उसकी तरफ से मध्यस्थता की कोई अपील नहीं की गई है। यह भी अहम है कि तीन दिन बाद रविवार को फ्रांस में ट्रंप की मोदी से भेंट के आसार हैं। दोनों वहां समूह-7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित होंगे। जाहिर है कि दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस बैठक में कश्मीर एक अहम मुद्दा रहेगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'उनके बीच (भारत व पाक) वर्षों से विभिन्न नामों के तहत बातचीत हो रही है, लेकिन यह कश्मीर है, जो बेहद पेचीदा जगह है। वहां हिंदू हैं, मुसलमान हैं और मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। दोनों तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जो दूसरी तरफ की सरकार का शासन चाहते हैं। दोनों देशों के बीच अभी स्थिति बहुत खतरनाक है। मैंने पीएम इमरान खान और नरेंद्र मोदी से बात की है। दोनों बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन कश्मीर की स्थिति कठिन है। वहां भारी हथियारों से गोलीबारी हो रही है। मैं सप्ताहांत में पीएम मोदी से मिलूंगा। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच इस बड़ी समस्या को सुलझाने में मध्यस्थता या किसी और तरीके से मदद कर सकता हूं। वहां जो कुछ है उसमें धर्म का बड़ा हाथ है। धर्म एक उलझा हुआ मुद्दा है।''

ज्ञात हो, पिछले एक माह में यह तीसरा मौका है जब ट्रंप ने मध्यस्थता की बात की है। सबसे पहले जब इमरान ने उनसे वाशिंगटन में भेंट की थी तब ट्रंप ने कहा था कि मोदी ने उनसे कहा है कि वह कश्मीर पर मध्यस्थता करें। इसकी भारत ने पुरजोर शब्दों में निंदा की थी। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया कि ऐसा कोई आग्रह नहीं किया गया। ट्रंप ने कुछ ही दिन बाद फिर कहा, वह मध्यस्थता कर रहे हैं। जबकि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कश्मीर मुद्दे को भारत-पाक को आपसी वार्ता से ही सुलझाना होगा। ट्रंप के बयान पर भारत ने आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं जताई है। जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में सेना निकालने की कोशिश में जुटे ट्रंप इस तरह की बयानबाजी करके पाकिस्तानी हुक्मरानों को खुश करने की कोशिश में हैं।

डोनाल्ड ट्रंप — फाइल फोटो

सेना मुख्यालय के पुनर्गठन को राजनाथ की हरी झंडी

उप-सेना प्रमुख के अधीन बनेगा सेना में मानवाधिकार संगठन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती चुनौतियों और परिस्थितियों के अनुसार सेना को चुस्त-दुरुस्त रखने और उसकी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सेना मुख्यालय के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। सेना मुख्यालय की ओर से किए गए विस्तृत आंतरिक अध्ययन के आधार पर यह मंजूरी दी गई है। इस पुनर्गठन के अनुसार पहली बार सेना मुख्यालय में अलग से आंतरिक सतर्कता और मानवाधिकार विभाग गठित किया जाएगा। इसके अलावा सेना मुख्यालय से 206 अधिकारियों को फील्ड यूनिटों में भेजा जाएगा। इसमें तीन मेजर जनरल, आठ ब्रिगेडियर, नौ कर्नल तथा 186 लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर शामिल हैं।

राजनाथ सिंह — फाइल फोटो

सेना मुख्यालय में इस कवायद के जरिए उन विभागों को बंद किया जाएगा जिसमें एक ही तरह के काम में लोग लगे हुए हैं। बता दें कि मौजूदा स्थिति में सेना मुख्यालय में लगभग 1000 सैन्य अधिकारी तैनात हैं। कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और सेना मुख्यालय को नई शक्ल देने की दिशा में ये फैसले लिये गये हैं। ऐसा पहली बार होगा जब सेना मुख्यालय में मानवाधिकार विभाग गठित किया जाएगा, जो अधिकारों के हनन के मामलों को देखने के लिए नोडल संस्था होगी। इसमें मानवाधिकार से जुड़े मामलों का संज्ञान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी लेंगे। इसके बाद रिपोर्ट को सेना के उप प्रमुख को सौंपा जाएगा। ज्ञात हो, सेना अक्सर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों का सामना करती है। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां वह सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) के तहत काम करती है।

सतर्कता शाखा में वायुसेना और नौसेना के प्रतिनिधि भी : सेना प्रमुख के नेतृत्व में स्पेशल विजिलेंस सेल का गठन किया जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से काम करेगी। इस सेल में वायुसेना और नौसेना के भी प्रतिनिधि होंगे। अभी यह काम अनेक एजेंसियां करती हैं। इसके लिए फिलहाल कोई केंद्रीकृत विभाग मौजूद नहीं है। इस शाखा का प्रमुख, अतिरिक्त महानिदेशक स्तर का अधिकारी होगा।

सेना ने चार अध्ययन कराए थे पेज>>6

सैन्य सुधार के कदम

- तीनों सेनाओं के प्रतिनिधित्व सहित सेना प्रमुख के अधीन होगा सतर्कता प्रकोष्ठ
- सेना मुख्यालय के 206 अधिकारी फील्ड यूनिटों में होंगे तैनात, इनमें तीन मेजर जनरल होंगे शामिल

वियतनाम में ओएनजीसी के तेल ब्लाक पर चीन ने तटरक्षकों के दल को किया तैनात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बीजिंग ने साउथ चाइना सी में उठाया अशोभनीय कदम
- गत माह ही वियतनाम ने भारत को दिया था चीन की करतूतों का ब्योरा

भारत को परेशान करने के लिए चीन की नई करतूत सामने आई है। साउथ चाइना सी में वियतनाम की समुद्री सीमा में स्थित भारत की सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी के तेल ब्लाक के पास चीन ने तटरक्षकों के बड़े दल को तैनात किया है। जिस क्षेत्र में ओएनजीसी का ब्लाक है वहां वियतनाम ने अपना आर्थिक क्षेत्र बना रखा है लेकिन चीन उस पर लगातार दावा करता रहता है।

जानकारी के मुताबिक, चीन वहां पहले भी कई बार समुद्री सीमा का उल्लंघन कर चुका है, लेकिन इस बार का उल्लंघन ज्यादा बड़ा है। चीन की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया है कि ओएनजीसी के तेल ब्लाक के पास उसके तट रक्षकों का पोत तैनात हो। वैसे पहले भी चीन उसके आसपास के क्षेत्र में अपने तट रक्षकों को भेजता रहा है लेकिन यह पहला मौका है जब ओएनजीसी के करीब उन्हें तैनात किया गया है।

ओएनजीसी का जहां पर यह तेल ब्लाक है उस इलाके पर चीन पहले भी कई बार दावा कर चुका है। वह कई बार भारतीय कंपनी की तरफ से वहां तेल ब्लाक हासिल करने के फैसले पर भी सवाल उठाता रहा है। उस क्षेत्र में ओएनजीसी के दो तेल ब्लाक हैं। 06.1 नाम से चिह्नित एक ब्लाक में ओएनजीसी की हिस्सेदारी 45 फीसद है, जबाकि 128 नाम के दूसरे ब्लाक में 100 फीसद हिस्सेदारी है। दोनों ब्लाकों में ओएनजीसी की सहायक ओएनजीसी विदेश ने निवेश किया है। ओएनजीसी ने हाल ही में इन दोनों ब्लाकों को दूसरे ब्लाकों से हस्तांतरित करने की संभावना पर विचार किया था।

साउथ चाइना सी पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का स्पष्ट निर्देश आने के बावजूद चीन उसे स्वीकार नहीं करता है। साउथ चाइना सी में तेल व गैस के बहुत बड़े भंडार होने की सूचना है। यहां स्थित दूसरे देश जैसे फिलीपींस, ब्रूनेई भी अलग अलग क्षेत्रों पर दावा करते हैं। इस बारे में वियतनाम की तरफ से भी भारत को लगातार सूचना दी जा रही है कि किस तरह से चीन की तरफ से ओएनजीसी समेत दूसरे तेल ब्लाकों को प्रभावित किया जा रहा है।

चांद की दूसरी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान-2

बेंगलुरु : भारत का चंद्रयान-2 कदम-दर-कदम मंजिल की ओर बढ़ रहा है।

बुधवार को इसने एक और अहम पड़ाव पार कर लिया। यान चांद की दूसरी कक्षा में पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कक्षा में बदलाव के बाद बताया कि चंद्रयान-2 के सभी उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं। बुधवार दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर यान की कक्षा में बदलाव किया गया। अगला बदलाव 28 अगस्त को सुबह साढ़े पांच से साढ़े छह बजे के बीच होना है। 22 जुलाई को रवाना हुए चंद्रयान-2 ने तीन हफ्तों तक पृथ्वी की कक्षाओं में चक्कर लगाया था। (पेज-16)

खरी बात

मामला कानूनी है लेकिन राजनीति का सवाल उठा रहे हैं चिदंबरम और उनकी पार्टी, जांच एजेंसियों की नजरों से ओझल रहने के बाद की प्रेस कांफ्रेंस, खुद को निर्दोष बताया

आरोप के बजाय इतिहास में झांकें चिदंबरम व कांग्रेस

त्वरित टिप्पणी
प्रशांत मिश्र

चौबीस घंटे से अधिक समय तक सीबीआइ और ईडी की टीम की पहुंच से बाहर रहे चिदंबरम साहब अब अवतरित हुए। प्रेस कांफ्रेंस की और फिर से यही जताया कि वह निर्दोष हैं और उन्हें बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। न्याय का तकाजा भी याद दिलाया। ध्यान रहे कि हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से साफ मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता है चिदंबरम साहब का केस इतना जरूरी है कि तत्काल सुन लिया जाए। यानी पूरा मामला कानून का है और सवाल राजनीति का उठाया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव में चिदंबरम को गलत फंसाया जा रहा है। राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं लेकिन कांग्रेस को और खासकर चिदंबरम को इतिहास में झांककर याद कर लेना चाहिए कि उस समय कैसी राजनीति हुई थी जब गुजरात दंगे और इशरत जहां मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को फंसाया गया था। घंटों तक उन्हें एसआइटी और सीबीआइ के दफ्तर में बिठाया गया था। हर पहलू पर कोर्ट ने दोनों को क्लीन चिट दिया था। यहां कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं मिली है।

गुजरात दंगे को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान चला था। चौतरफा घेरने की कोशिश हुई थी। उन्हें एसआइटी में जाकर सफाई देनी पड़ी थी और आखिरकार कोर्ट ने उन्हें बरी किया। अमित शाह के मामले में तो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय और तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम का हस्तक्षेप साबित हुआ था। जब आतंकी इशरत जहां का मामला आया तो चिदंबरम के अंडर सेक्रेटरी आरबीएस मणी ने एफीडेविट देकर कहा कि खुफिया विभाग की रिपोर्ट पुख्ता नहीं है। इसीलिए सीबीआइ जांच होनी चाहिए। दरअसल खुफिया विभाग का मानना था कि इशरत जहां आतंकी है, लेकिन तत्कालीन सरकार चाहती थी कि उसे निर्दोष साबित कर हत्या का दोष शाह पर मढ़ा जाए।

ध्यान रहे कि पहले आरबीएस मणी ने कोर्ट में खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगाई थी। पूरी बात तब सामने आई जब मणी ने ही बताया कि चिदंबरम के कहने पर उन्होंने खुफिया विभाग की रिपोर्ट को गलत बताते हुए सीबीआइ जांच की मांग की थी। साफ था कि मामला राजनीति से प्रेरित था। बाद में क्या हुआ सभी जानते हैं। शाह को कई बार सीबीआइ ने बिठाया, पूछताछ की, चार्जशीट दाखिल की और गिरफ्तार किया। उन्हें ढूंढने के लिए सीबीआइ को दौड़ नहीं लगानी पड़ी। चिदंबरम साहब सीबीआइ और ईडी को दौड़ा रहे हैं।

बताया जाता है कि 2018 में जब ईडी ने चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति को बुलाया था तो वह पहले ही जमानत लेकर वहां गए थे। आखिर वह इतने डरे हुए क्यों थे? वह तो खुद बहुत ही तेज तर्रार वकील हैं, पूछताछ का सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं...। ईडी का कहना है कि पूछताछ में भी वह हर बात को झुठलाते रहे जबकि दस्तावेजी सबूत कुछ और कहते हैं। अब राहुल गांधी, प्रियंका समेत कांग्रेसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति के कारण चिदंबरम को फंसाया गया है। उन्हें भी पहले यह बताना चाहिए कि मणी के बारे में वह क्या कहेंगे। हाई कोर्ट को वह संतुष्ट नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट उनकी बेचैनी से प्रभावित नहीं है। कोर्ट में तो उन्हें बताना होगा कि ईडी के दस्तावेजी सबूत के खिलाफ उनके पास ऐसा क्या है जो चिदंबरम साहब को निर्दोष साबित करता है।

बंदूक उठाने वाले अब तिरंगे को मुस्तकबिल मानने को तैयार

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर की सियासत पर्दे के पीछे से नई करवट ले रही है। ऑटोनामी और आजादी के नारों की सियासी दुकान पर ताला क्या लगा जिहाद के लिए बंदूक उठाने वाले तिरंगे को अपना मुस्तकबिल मानने को तैयार हो गए हैं। मुख्यधारा में लौटने के लिए बंदूक से किनारा कर चुके कई पूर्व आतंकी अब नया सियासी संगठन खड़ा कर फरेब की सियासत को जवाब देने की तैयारी में हैं। जल्द ही नए संगठन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। (पेज-5)

ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर पहली सितंबर से लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली : यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले वाहन चालक सावधान हो जाएं। नए मोटर एक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें पहली सितंबर से कई गुना अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार नए मोटर एक्ट के प्रावधानों को एक सितंबर से लागू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इसका एलान किया। (पेज-6)

डॉ. मिश्र के गार्ड ऑफ ऑनर में धोखा दे गईं पुलिस की राइफलें

जागरण टीम, सुपौल

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र का बुधवार को सुपौल के बलुआ बाजार गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि इस दौरान बिहार पुलिस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब डॉ. मिश्र को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, तब 22 पुलिसकर्मियों में से एक की भी राइफल से गोली नहीं चली। खास बात यह रही कि बिहार पुलिस की यह बेइज्जती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हुई। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो जवानों ने फायरिंग का प्रयास किया, लेकिन एक भी फायर संभव नहीं हो सका। मुख्यमंत्री के वहां से जाने के बाद लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा होने लगी। कोसी रेंज के डीआइजी सुरेश चौधरी ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, गार्ड ऑफ ऑनर ब्लैंक कार्टेज से दी जाती है, जो फायर नहीं हुआ। मामले की जांच कराई जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए फायर करने की कोशिश करते पुलिसकर्मी। जागरण

यह होता है ब्लैंक कार्टेज : गार्ड ऑफ ऑनर देने या गोली का डेमो करने के लिए ब्लैंक कार्टेज का उपयोग होता है। विशेष तरह की इस गोली में छर्रा नहीं होता है। सिर्फ बारूद भरी होती है, जिससे आवाज निकलती है। इसकी सप्लाई पुलिस विभाग में अलग से की जाती है। जानकार बताते हैं कि काफी दिनों से पुलिस को ब्लैंक कार्टेज की सप्लाई नहीं की गई है। पुरानी सप्लाई को ही सुरक्षित रखकर उसका उपयोग किया जा रहा है।